



सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र)

फरवरी-मार्च, 2024 की कार्यसूची

(खण्ड-04)

दिनांक- 23 फरवरी, 2024

माँग संख्या - 10

आय-व्ययक शीर्षक - ऊर्जा विभाग

87. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "ऊर्जा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11422,67,80,000/- (ग्यारह हजार चार सौ बाईस करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 88-91. श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक - ग्रामीण विकास विभाग

92. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "ग्रामीण विकास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 14296,71,15,000/- (चौदह हजार दो सौ छियानवे करोड़ इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 93-95. श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक - गृह विभाग

96. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "गृह विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 16323,83,06,000/- (सोलह हजार तीन सौ तेईस करोड़ तिरासी लाख छः हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 97-98. श्री राजेश कुमार एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक - सामान्य प्रशासन विभाग

99. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सामान्य प्रशासन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1025,11,46,000/- (एक हजार पच्चीस करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

100. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक - भवन निर्माण विभाग

101. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "भवन निर्माण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 5012,65,48,000/- (पाँच हजार बारह करोड़ पैसठ लाख अड़तालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

102. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक - विधान मंडल

103. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विधान मंडल" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 284,30,12,000/- (दो सौ चौासी करोड़ तीस लाख बारह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक - समाज कल्याण विभाग

104. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "समाज कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 8238,56,50,000/- (आठ हजार दो सौ अड़तीस करोड़ छप्पन लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 105-106. श्री राजेश कुमार एवं अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

107. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 674,55,28,000/- (छः सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख अट्ठाईस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

108. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

109. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1802,72,84,000/- (एक हजार आठ सौ दो करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

110. श्री राजेश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

111. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 648,65,89,000 /- (छः सौ अड़तालीस करोड़ पैंसठ लाख नवासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

112. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 467,24,73,000/- (चार सौ सड़सठ करोड़ चौबीस लाख तिहतर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक - निगरानी विभाग

113. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "निगरानी विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 45,59,71,000/- (पैंतालीस करोड़ उनसठ लाख इकहतर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

114. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।


राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक - निर्वाचन विभाग

115. प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "निर्वाचन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 848,32,52,000/- (आठ सौ अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख बावन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।



(राज कुमार)
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 645 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 645 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 645 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।


21/2/24